

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) - जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई  
2. प्रकरण संख्या : 2/2024  
3. उनबान : सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

- प्रार्थी

बनाम

1. सांवरमल पुत्र घीसा
  2. मंजू पुत्री घीसा
  3. हंसा पुत्री घीसा
  4. परमेश्वरी पुत्री घीसा
  5. सुमन पुत्री घीसा
  6. मोहरी पत्नी घीसा.
- समस्त जाति जाट निवासी गदडी।

- अप्रार्थी

4. निर्णय दिनांक : 28/09/2025  
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) सरकार पैरोकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) में अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम तुर्कियावास की चालु जमाबन्दी संवत् 2076 (वर्ष 2019) में स्थाई के खाता स० 165 में घीसा पुत्र तेजा हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा० गदडी गैरखातेदारी के नाम खसरा नं० 41/5 रकबा 2.5290 है० किस्म बालनी 3 दर्ज है। उक्त आवंटी भूमि को दिनांक 11.06.1968 में कृषि हेतु आवंटित की गई। इन्का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण संख्या 32 से हुआ, जो तत्समय आवंटित भूमि का मूल खसरा नं० 41 रकबा 62 बीघा 08 बिस्वा किस्म 50 बीघा बंजर अब्बल 12 बीघा 28 बिस्वा गै०मु० तलाई दर्ज थी। जिसमें से कुल पांच व्यक्तियों को भूमि आवंटन हुई थी।

पंचम आवंटी काना पुत्र तेजा कोम जाट निवासी गदडी खसरा नंबर 41/2 रकबा 2.5290 है०  
द्वितीय आवंटी घीसा पुत्र तेजा कोम जाट निवासी गदडी खसरा नं० 41/5 रकबा 2.5290 है०  
तृतीय आवंटी भूरा पुत्र गोलू कोम जाट निवासी गदडी खसरा नं० 41/4 रकबा 2.5290 है०  
चतुर्थ आवंटी मूल्या पुत्र चिम्ना कोम जाट निवासी गदडी खसरा नं० 41/3 रकबा 2.5290 है०  
पंचम आवंटी बालू पुत्र रुडा कोम जाट निवासी गदडी खसरा नं० 41/1 रकबा 2.5290 है०  
जिसमें से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नं० 41/3 रकबा 2.5290 किस्म गै०मु० तलाई खसरा नं० 1041/1 रकबा 2.5290 किस्म गै०मु० तलाई, खसरा नं० 41/2 रकबा 2.5290 है० किस्म गै० मु० तलाई कुल 3 आवंटियों का आवंटन निरस्त मुताबिक न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर प्रकरण संख्या रेफरेंस एल.आर./5639/2006/जयपुर निर्णय दिनांक 20.11.2013 व न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर प्रकरण संख्या रेफरेंस एल.आर./5635/2006/जयपुर निर्णय दिनांक 18.04.2012 व रेफरेंस एल.आर./5625/2006/जयपुर निर्णय दिनांक 14.03.2012 को जरिये नामान्तरण संख्या 659, 991, 1042 द्वारा निरस्त होकर जमाबन्दी में अमल दरामद हो गया है। उक्त प्रकरण में तत्समय वर्ष

20 7  
अतिरिक्त, जिला कलक्टर  
(तृतीय) जयपुर





देशीय सरकार द्वारा अपनी बहस के समर्थन में तहसीलदार फुलेरा के अलावा अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के प्रकरण संख्या 182/68 निर्णय दिनांक 03.09.1969 तथा प्रकरण संख्या 2/95 निर्णय दिनांक 25.11.1995, अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय के प्रकरण संख्या 76 से 80 निर्णय दिनांक 14.07.1997, राजस्व अपील अजमेर के निर्णय दिनांक 05.08.1997, राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 19.08.1998, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.08.2005, अति० जिला कलक्टर जयपुर के प्रकरण संख्या 328/2005 निर्णय दिनांक 08.09.2006, मा० न्यायालय राजस्थान अजमेर के रेफरेंस संख्या 5625/2006 निर्णय दिनांक 14.03.2012, मा० न्यायालय राजस्थान मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेंस संख्या 5635/2006 निर्णय दिनांक 18.03.2012 एवं इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 10/2018 तथा 34/2018 निर्णय दिनांक 27.09.2024 की प्रति पेश की है।

पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन के अनुसार विवादित भूमि वर्तमान में खाली में चल रही है।

प्रकरण में ग्राम जनता तुर्कियावास द्वारा एक अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार फुलेरा दिनांक 11.06.1968 व 20.01.1969 बाबत अलाटमेंट भूमि खसरा नं० 144, 146-41-22 बाबत ग्राम तुर्कियावास न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में पेश की गयी। जिसका मुकदमा नं० 182/68 दर्ज हुआ। उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 03.09.1969 को पारित किया गया। निर्णयानुसार "अलाटमेंट की कुल कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है और यह सिद्ध है कि कुल कार्यवाही ग्रामवासियों को छिपाकर बगैर सोचे विचारे व नियमों की अनुपालना पूर्ण न होने की गयी है। अतः उपरोक्त कारणों की बिनाय पर में हर दो अपीलें स्वीकृत कर लिये जायें जो भूमि आवंटन आदेश दिये गये हैं उसको निरस्त करता हूँ और पत्रावली अतिरिक्त न्यायालय इस आदेश से लौटाता हूँ के तहसीलदार अगर अलाटमेंट करने हेतु भूमि आवंटन पर भूमि आवंटन नियमों की पूरी तरह से पालना व पूर्ति कर निर्णय दे। आज्ञा जारी गयी तारीख 03.09.69"

संलग्न भूमि खसरा नंबर 41 रकबा 62 बीघा 08 बिस्वा के क्रम में एक 14(4) का प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय, जयपुर के न्यायालय में ग्रामवासियों द्वारा पेश किया गया था। प्रार्थना पत्र संख्या 76 से 80 में न्यायालय अति० जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 14/07/1997 में "अप्रार्थीगण का भूमि पर कब्जा नहीं रहा है एवं भूमि आम जनता के उपयोग में आती रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फुलेरा द्वारा किया गया आवंटन दिनांक 11/06/1968 निरस्त किया जाता है।"

उक्त भूमि के आवंटियों द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय, जयपुर के निर्णय दिनांक 14/07/97 के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 05.08.1997 द्वारा अपील स्वीकार कर उक्त भूमि का आवंटन बहाल रखा गया।

उक्त भूमि के क्रम में राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 05.08.1997 के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील प्रस्तुत किया गया।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर  
(द्वितीय) जयपुर

जाने पर उनके निर्णय दिनांक 19.08.1998 द्वारा अपील को खारिज किया जा कर माननीय राजस्व मण्डल राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 05.08.1997 को यथावत रखा गया।

उक्त भूमि के क्रम में राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 19.08.1998 के क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में आम जनता द्वारा प्रस्तुत एम0बी0मिडिल पेटिशन संख्या 2388/1999 के निर्णय दिनांक 11.08.2005 में राजस्व अपील प्राधिकारी को पुनः दर्जा देने के हुना जाने एवं याचिकाकर्ताओं को राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील में स्वतः ही स्वीकार माना जाने के आदेश पारित हुये।

उक्त भूमि के क्रम में तहसीलदार द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 82 एल.आर.एक्ट इन्ड्रान्ज फुलेरा बजट खसरा नं0 41/5 रकबा 10 बीघा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बलूरा न्यायालय में पेश किया। जिसमें निर्णय दिनांक 08.09.2006 में निर्णय पारित करने के आदेश दिये कि उक्त भूमि गै0मु0 तलाई दर्ज है जिसका आवंटन प्रतिकूल है। अतः तहसीलदार माननीय राजस्व मण्डल में नियमानुसार रेफरेंस प्रस्तुत करें।

उक्त भूमि खसरा नं0 41/2 रकबा 10 बीघा के संबंध में तहसीलदार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेंस प्रार्थना पत्र 5625/2006 पेश किया गया जिसके निर्णय दिनांक 14.03.2012 में उक्त भूमि में से आवंटन भूमि ख0नं0 41/2 रकबा 10 बीघा को सिवायक गै0मु0 तलाई दर्ज करने का आदेश तहसीलदार फुलेरा को दिया गया। न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह भी अंकित किया है कि "यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति भी जागरूक है कि इस निर्णय से अप्रार्थी के अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। अतः यह न्यायालय इस प्रकरण में संबंधित उपखण्ड अधिकारी को यह निर्देश देना भी उचित समझता है कि प्रसंगत भूमि पर अस्थाई काश्त हेतु अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व (अस्थाई काश्त हेतु तालाब पेटे की भूमि का आवंटन) नियम 1961 के अन्तर्गत नियमानुसार आवंटन किये जाने पर विचार किया जावे जिसमें उसकी रोजी-रोटी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो"

उक्त भूमि खसरा नं0 41 में से खसरा नं0 41/1 रकबा 10 बीघा भूमि के संबंध में अन्य रेफरेंस संख्या 5635/2006 उनवान सरकार बनाम बालू माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में निर्णय दिनांक 18.04.2012 में रेफरेंस स्वीकार कर आवंटन एवं अन्य सभी अंकन निष्पत्ति किया जाकर विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में पुनः राजकीय गै0मु0 तलाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये।

उक्त भूमि खसरा नं0 41 में से दो आवंटन के विरुद्ध तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत धारा 82 एल.आर.एक्ट दुर्गुस्ती प्रार्थना पत्र संख्या 34/2018 एवं 10/2018 के संबंध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2024 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन 14(4) के श्रेणी में होना बताते हुये तहसीलदार द्वारा यह 14(4) के दो प्रकरण इस न्यायालय में पेश किये गये।

हमने सम्मानपूर्वक सभी न्यायालयों के निर्णयों को पढ़ा। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्डों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। निष्कर्ष यह है कि ग्राम तुकिवावास के खसरा नं0 41 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि वंजड में से 10-10 बीघा किरम बंजड अबल भूमि क्रमशः भीसा पुत्र काना पुत्र तेजा, मूला पिता चिमना, भूरा पुत्र भोलू एवं बालू पुत्र रुडा को अलौट हुयी। 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि किरम गै0मु0 तलाई भू-प्रबंध विभाग सैटलमेंट खाते में संवत् 1911-29 में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार तीन प्रकरण तहसीलदार

जतिविला, जिला कलक्टर  
(पुलव) जयपुर

किशनगढ रेनवाल रेफरेंस संख्या एल.आर/5625/2006, एल.आर/5635/2006 एवं एल.आर/5639/2006 प्रस्तुत किये। संबंधित भूमि खसरा नं० 41/1, 41/2 एवं 41/3 में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भूमि को गै०मु० तलाई बताते हुये आवंटन निरस्त किये गये हैं। यद्यपि उक्त तीनों आवंटन बंजड भूमि में किए गए थे तथा 02 रेफरेंस प्रकरण एल.आर/5634/2006 एवं एल.आर/1342/2007 में क्रमशः दिनांक 28/06/2013 एवं 06/03/2013 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने रिमाण्ड करते हुए पुनः परीक्षण प्रस्ताव निर्णय पारित करने के निर्देश दिये। शेष भूमि खसरा नं० 41/6 रकबा 12 बीघा 8 आबादी संवत् 2048-49 में गै० मु० तलाई दर्ज रिकार्ड है। जिसमें से 5 बीघा भूमि पश्चात को आबादी हेतु आवंटन की गयी जो कि गै०मु० तलाई आरटीए की धारा 16 में उल्लंघन की भूमि होने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने योग्य पाया गया। शेष 7 बीघा 8 डिस्वा भूमि खाली होना बताया है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं खसरा गिरदावरी की नकलों के अनुसार संवत् 2048 में अप्रार्थी द्वारा 10 बीघा कृषि भूमि पर ग्वार काशत की गई। इस प्रकार आवंटी घीसा काशत द्वारा एक बार ही काशत की गई है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि खसरा नंबर 41/5 पर केवल एक बार कब्जा काशत किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार एवं नियमानुसार कब्जा नहीं रहा है। अतः राजस्थान भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन शर्तों का पालन नहीं होने के कारण भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 41/5 रकबा 2.5290 हैक्टेयर में 0.3949 हैक्टेयर तक कब्जा बना हुआ है व 0.0800 हैक्टेयर भूमि पर एक विश्राम गृह बना हुआ है। शेष भूमि पर अन्य व्यक्तियों का अतिक्रमण है। कब्जेधारियों द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट है कि कृषि भूमि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। अतः आवंटन निरस्त भूमि खसरा नं० 41 में 50 बीघा भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा वरवक्त आवंटन नियमों का पालन नहीं किये जाने एवं आवंटी द्वारा पश्चात आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है।

अतः तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम दर्जशुदा भूमि खसरा नं० 41/5 रकबा 2.5290 हैक्टेयर ग्राम तुरक्यावास तहसील किशनगढ रेनवाल को पुनः आवंटन बंजड दर्ज करने एवं उसके पश्चात किये गये इन्द्राजात को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेंस किया जाता है। प्रकरण अनुसार रेफरेंस हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृन्तल विश्वा)   
 अति. जिला कलक्टर एवं   
 जिला अधीक्षक (रातीय)   
 जयपुर